5.5 सुधार के उपाय

लघु एवं कुटीर उद्योगों की समस्याओं के अध्ययन के पश्चात् यह आवश्यक है कि इन्हें किस प्रकार सुधार जाय, स बात पर भी विचार हो। इन उद्यांगों के सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं :

(1) उत्पादन तकनीक में सुधार (Improvement in Prodution technique)—लघु एवं कुटीर उद्योग के सुधार के लिए उत्पादन के उत्तम तकनीक अपनाये जाने चाहिए जिसं उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म

Scanned with CamScanner

को वस्तुएँ मिल सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक लघु उद्योग इकाई अपनी वार्षिक आय का लगभग 10 प्रतिशत एक विशेष कोष में हस्तांतरिक करें जिसका उपयोग आधुनिकीकरण पर हो और यह कोष कर मुक्त भी रहे ।

(2) सलाहकार फर्मों की व्यवस्था (Establishment of Consultancy firms)—लघु उद्योगों की स्थापना करने, विकास करने और मशीनों इत्यादि के प्रयोग करने के लिए पर्याप्त सलाहकार सेवाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

(3) लघु उद्योग सहकारी समितियों का विकास (Develpment of Small Industries Cooperative Societies)— लघु एवं कुटीर उद्योगों की समस्या के समाधान के लिए सहकारी समितियों का विकास किया जाना चाहिए जिससे कि ये समितियाँ अपने सदस्यों को उचित मूल्य पर उन्नत उपकरण और कच्चा माल उपलब्ध करा सकें ।

(4) विशाल एवं लघु उद्योगों में समन्वय (Integration of small scale industies with modern larger scale indisties)—बड़े एवं छोटे उद्योगों के बीच समन्वय होना भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए कागज उद्योगों में लुग्दी बनाने का काम लघु उद्योग क्षेत्र को सौंप कर मन्वय स्थापित किया जा सकता है ।

(5) अनुसंधान कार्यक्रमों की विस्तृत व्यवस्था (Vigorous System of Research)--लघु उद्योगों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए विस्तृत रूप में अनुसंधान की व्यवस्था होनी चाहिए ।

(6) उत्पादन की किस्म पर उचित नियन्त्रण (Control on Quality of Producitor)—लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करने तथा उपभोक्ताओं में विश्वास बनाये रखने के लिए इन उद्योगों की उत्पादन किस्म पर उचित नियन्त्रण भी आवश्यक है ।

5.6 नियोजन एवं इसकी आवश्यकता

नियोजन शब्द के अर्थ या अभिप्राय के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में भी मतान्तर है। कुछ अर्थशास्त्रियों में नियोजन का अर्थ किसी अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप एवं नियन्त्रण (Government intervention and control) से लगाया है, तो कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने नियोजन का अर्थ किसी देश में गठित किसी केन्द्रीय अधिकारी (Central Authority) से लगाया है। कुछ दूसरे अर्थशास्त्रियों ने इसका अभिप्राय समाजवाद से लगाया है। इसके आकरण नियोजन के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गयी है। अतः इस पाठ के प्रारम्भ मे हमलोग नियोजन शब्द की विभिन्न परिभाषाओं की व्याख्या एवं समीक्षा करें जिससे इसका सही अर्थ एवं स्वरूप स्पष्ट हो जायेगा तथा बाद में विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्था में इसकी आवश्यकता या अनिवार्यता पर विचार करेंगे ।

Scanned with CamScanner

5.6.1 नियोजन का अर्थ या अभिप्राय एवं परिभाषायें –

प्रो० रॉबिन्सन के अनुसार, "Planning in modern jargon involve Government control of production in some from or the other." अर्थात् आधुनिक शब्दावली में नियोजन का अभिप्राय उत्पादन पर किसी न किसी प्रकार के सरकारी नियंत्रण से लगाया जाता है । यह बात बिल्कुल ठीक है कि नियोजन में या किसी भी नियोजित अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादक क्रियाओं पर किसी-न-किसी प्रकार का सरकार नियंत्रण रहता है । परन्तु आज अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर किसी प्रकार के सरकारी नियंत्रण मात्र को नियोजन नहीं कहा जा सकता है । आज विश्व के प्राय: सभी देशों में तथा सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था पर किसी प्रकार का सरकारी नियंत्रण रहता ही है । अठारहवीं शताब्दी में ही अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ (Adam smith) ने भी स्वीकार किया था कि देश में आन्तरिक अमन-चैन एवं सुव्यवस्था के लिये, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए तथा लोगों की विभिन्न प्रकार की सामहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक क्रियाओं के संचालन में सरकारी हस्तक्षेप एवं नियंत्रण परमावश्यक है। परन्तु इस प्रकार के हस्तक्षेप एवं नियंत्रण मात्र को नियोजन नहीं कहा जाता है।

प्रो०हेबक (Habek) ने नियोजन शब्द का अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था में किसी केन्द्रीय अधिकारी द्वारा उत्पादक क्रियाओं के नियंत्रण से लगाया है । उनके ही शब्दों में, "The term economic planning means the directionof productive activity by a central authority) प्रो० हेबक की यह बात ठीक है कि नियोजन में यह नियोजित अर्थव्यवस्था में एक केन्द्रीय अधिकारी होता है जो देश या अर्थव्यवस्था के समस्त आर्थिक क्रिया-कलापों को निर्देशित करता है। परन्तु यह केन्द्रीय अधिकारी या उनके द्वारा उत्पादक क्रियाओं का निर्देशन नियोजन नहीं है। फिर भी, उनकी नियोजन की परिभाषा से यह स्पष्ट नही होता है कि नियोजन में केन्द्रीय अधिकारी के निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है तथा उसके क्या-क्या लाभ या हानियाँ अर्थव्यवस्था में होती हैं। इत्यादि बातें स्पष्ट नहीं हो पाती है। वास्तव में, नियोजन मे केंद्रीय अधिकारी द्वारा अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्रियाओं का निर्देशन सतत् या लगातार या अनवरत रूप से होता रहता है। यह निर्देशन देश की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये इसके उत्पादक साधनों के विवेकपूर्ण आवंटन द्वारा तथा नये उत्पादक साधनों के सृजन द्वारा भी होता रहता है। अर्थात् नियोजन एक सतत् दीर्घकाल प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिये देश के समस्त भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का आवंटन होता है, जिसमें न केवल अधिकाधिक वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, वन उनका न्यायोचित वितरण भी होता है ।

नियोजन की इस महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करते हुए बराबर ऊअन ने नियोजन की परिभाषा दी है। उनके अनुसार, "Planning is conscious deliberat hoice of economic proioriteis by some public authorities." अर्थात् किसी अर्थव्यवस्था में या देश में राजकीय अधिकारियों द्वारा सविचार एवं विवेकपूर्ण ढंग से प्राथमिकताओं का निर्धारण करना ही नियोजन कहलाता है। नियोजन में सरकारी अधिकारियों या योजनाधिकारियों द्वारा आर्थिक प्राथमिकताओं का विवेकपूर्ण ढंग से निर्धारण किया जाता है और उसी के अनुसार देश के समस्त

Scanned with CamScanner

संसाधनों का विभिन्न क्षेत्रों में आवंटन करने का प्रयास किया जाता है । यह प्रयास ऐच्छिक है और नियोजन की धारा का अनिवार्य अंग है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में बाजार की शक्तियां द्वारा स्वतः उत्पादन साधनों का विभिन्न क्षेत्रों में आवंटन एवं तदनुरूप विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, विनिमय एवं वितरण होता रहता है, इसे नियोजन नहीं कहा जा है। नियोजन में अधिकारियों द्वारा सोच-समझकर देश के संसाधनों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न उद्देश्य निर्धारित किये जात हैं तथा इन विभिन्न उद्देश्यों की प्राथमिकतायें भी निर्धारित की जाती है। इन निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुरूप देश के संसाधनों का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। नियोजन की इस बातों का उल्लेख बारबरा ऊटन के नियोजन की परिभाषा में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है । परन्तु इन बातों के अलावे, नियोजन में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के सापेक्षिक मूल्यों के निर्धारण तथा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के वितरणों की न्यायोचित व्यवस्था भी की जाती है। ये बातें भी नियोजन की धारणा के आवश्यक अंग है जिसका उल्लेख ऊटन की नियोजन की परिभाषा में नहीं किया गया है ।

नियोजन में सन्निहित उपरोक्त बातों का उल्लेख करते हुए एच० डी० डीकिन्सन (H. D. Dickinson) ने नियोजन की परिभाषा दी है । उनके शब्दों में, "Economic planning is the making of major economic decisions what and how much isn to be produced and to whom it is to be allocated by the conscious delliation of a dterminate authority on the basis of comprehensie survey of ecomic system as a whole." अर्थात् आर्थिक नियोजन प्रमुख आर्थिक निर्णयों का निर्माण है जिसमें अर्थव्यवस्था के व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर एक निर्धारक सत्ता के द्वारा विवेकपूर्वक यह निर्धारित किया जाता है कि क्या एवं कितना उत्पादन कियाजाय और इसे कैसे वितरित किया जाय। इस प्रकार नियोजन का अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था में सभी महत्वपूर्ण निर्णयों के निर्धारण से लगाया जात है, देश में किन वस्तुओं का उत्पादन कियां जाय उनकी कितनी मात्राओं का उत्पादन किया जाय, उन्हें विभिन्न साधनों को किस अनुपात में लगाकर उत्पादन किया जाय, उत्पादित वस्तुओं की कीमतें कितनी हो तथा उनका न्यायोचित वितरण किस प्रकार किया जाय इत्यादि। उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण निर्णयों के निर्धारण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को नियोजन कहा जाता है जो एक गतिशील दीर्घकालीन, श्रमिक समाजवादी सम्पूर्ण प्रक्रिया है ।

नियोजन की डिकिन्सन की परिभाषा के अनुरूप भारत के प्रथम योजना आयोग ने भी नियोजन की परिभाषा दी । प्रथम योजना आयोग के अनुसार, "Economic planning is essentially a way of organizing and utilizing resources to the maximum advantages in terms of defined social ends. The two imortant aspects of the concepts of planning are (I) a system of ends to be persued and (II) knowledge as to the aailable resources and their optimum allocaiton." अर्थात् नियोजन एक

Scanned with CamScanner

तरीका या पद्धति है जिसके द्वारा देश के समस्त उत्पादक साधनों का उपयोग अधिकतम मात्रा में लाभ की प्राप्ति के लिये किया जाता है । नियोजन के दो महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं (I) उद्देश्यों का निर्धारण करना तथा (II) उनके लिये उपलब्ध साधनों की जानकारी प्राप्त करना तथा उनका सर्वोत्तम आवंटन करना ।

नियोजन की उपरोक्त परिभाषाओं से ज्ञात होता है कि यह एक दीर्घकालीन गतिशील सम्पूर्ण समग्रवादी प्रक्रिया है जिसमें देश में नियुक्त योजनाधिकारियों द्वारा सभी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लिये जाते हैं और उन्हें उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यान्वित किया जाता है । इसमे किसी देश के समस्त उत्पादक साधनों का सर्वोतम आवंटन किया जाता है, उन्हें योजना मे निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में आवंटित किया जाता है, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के उपयुक्त मूल्य निर्धारित किये जाते हैं तथा उन्हें उनके उत्पादक साधनों के बीच समुचित रूप से वितरित किया जाता है, जिससे देश या समाज के अधिकतम लोगों की अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा सामाजिक कल्याण को अधिकतम किया जा सके । यह न केवल देश की वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने का एक कारगर तरीका है, वरन् भविष्य में उत्पन्न होनेवाली समस्याओं को रोकने या कम करने तथा उन्हें दूर करने का भी एक उपयुक्त उपाय है। अत: नियोजन या किसी नियोजित अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषतायें होती हैं जो अनियोजित स्वतन्त्र व्यवस्था से उसे भिन्न करती हैं :

(1) नियोजन विभिन्न समाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक उद्देश्यों को पूरा करने का एक कारगर तरीका या उपाय है ;

(2) यह किसी अर्थव्यवस्था की विभिन्न प्राथमिकताओं को निर्धारित करने का एक तरीका है;

(3) यह किसी अर्थव्यवस्था की विभिन्न समस्याओं एवं साधनों के सर्वेक्षण पर आधारित होता है;

(4) इसमें किसी अर्थव्यवस्था की समस्त आर्थिक क्रियाओं के सफल संचालन नियमन एवं नियंत्रण के लिये एक सर्वोच्च केन्द्रीय योजनाधिकारी होता है,

(5) इसमें न केवल सरकारी हस्तक्षेप वरन् आवश्यक सरकारी नियंत्रण भी परमावश्यक होता है ।

(6) सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण प्रयासों से अर्थव्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन होते रहते हैं।

(7) यह एक समाजवादी धारणा है जो समपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं इसके सम्पूर्ण आर्थिक क्रिया-कलापों से सम्बोधित होता है ।

(8) यह किसी अर्थव्यवस्था की सभी आर्थिक क्रियाओं को संचालित एवं नियंत्रित करने की एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है ।

Scanned with CamScanner